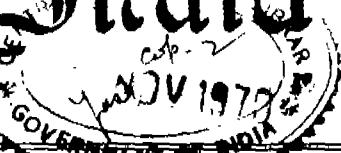




भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



लं. 46]

नई विल्सनी, शनिवार, नवम्बर 14, 1970 (कार्तिक 23, 1892)

No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 14, 1970 (KARTIKA 23, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—

—Nil—

उपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियाँ प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-घर पेजने पर घेज ही आएं।
मांग-घर प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने आहुएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.
321GI/70

विषय-सूची (CONTENTS)

भाग I—खंड 1—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर)	पृष्ठ	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ
भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	921	भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	4461
भाग I—खंड 2—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर)	1411	भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	599
भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	115	भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1293
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1369	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	437
भाग II—खंड 4—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—	भाग III—खंड 3—मुद्रण आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	165
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1859
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रकर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	199
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि समिश्रित हैं)	3607	पुरक संख्या 46— 7 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्टें	1907
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	921	17 अक्टूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा मरी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आकड़े	1917
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1411	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4461
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	115	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	599
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1369	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1293
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	437
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	165
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3607	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1859
Weekly Epidemiological Reports for week ending 7th November 1970	—	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	199
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 17th October, 1970	—	SUPPLEMENT NO. 46	1907
	3607		1917

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम प्रायालय द्वारा जारी की गई विधि०८ विधेयों, रिक्तियों तथा आवेदनों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

पोतपरिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय

सीमा सङ्कर विकास बोर्ड

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 1970

मं. एफ० ४(१९)/बी० आर० डी० बी०/प्रोजे०/६४—
जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स को सौंपे गए सङ्कों के विभागीय निर्माण में होने वाले खर्च को कम करने के प्रयत्न पर सरकार कुछ समय से विचार कर रही थी। मजदूरी और सामग्री पर आने वाली लागत में सामान्य रूप से बढ़ि हो जाने के कारण इस प्रयत्न पर विचार करना और भी महत्वपूर्ण हो गया था। इसलिए यह निर्णय किया गया कि निम्नलिखित रूप से बनाई गई एक समिति उन सब पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करेगी जिनके कारण जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा सीमा सङ्कों के निर्माण और उनके रख-रखाव पर इतना खर्च आ रहा है और माथ ही निर्माण कार्यक्रम की गति और कार्यदक्षता में किसी प्रकार की अवरुद्धता आए बिना सङ्कर निर्माण पर होने वाली लागत को यथा सम्भव कम करने के लिए सुझाव देगी।

गठन

1. श्री एस० एन० सिन्हा,	अध्यक्ष
महानिदेशक (सङ्कर विकास) और अपर सचिव, परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय	
2. श्री एस० के० छिब्बर,	सदस्य
सचिव, सीमा सङ्कर विकास बोर्ड	
3. श्री ए० बी० बी० कृष्णन,	सदस्य
संयुक्त सचिव, (वेतन आयोग तथा श्रम), वित्त मंत्रालय	
4. मेजर-जनरल जे० एस० ब्रावो, ए० बी० एस० एम०,	सदस्य
डाइरेक्टर जनरल सीमा सङ्कर	
5. श्री एच० सी० मल्होत्रा,	सदस्य
चीफ इंजीनियर-१, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	

सीमा सङ्कर विकास बोर्ड के उप-मन्त्रिव श्री बी० बी० छंग समिति के पूर्णकालिक सचिव रहेंगे।

विवारार्थ विषय

समिति निम्नलिखित विषयों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :—

- (क) सीमा क्षेत्रों की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्या सीमा सङ्कर संगठन द्वारा सङ्कों के निर्माण और रख-रखाव पर किया जाने वाले खर्च उपयुक्त है; यदि नहीं तो किन पहलुओं के कारण इतना अधिक खर्च हो रहा है? क्या इस खर्च की तुलना मार्वजनिक निर्माण विभाग जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा इसी प्रकार के सङ्कों के निर्माण तथा रख-रखाव पर किये जाने वाले खर्च से भी की जा सकती है।
- (ख) कौन से ऐसे अस्थायी और दूरगामी उपाय हो सकते हैं जिनमें निर्माण तथा रख-रखाव पर होने वाले खर्च घट सकता है। इस संबंध में विशेष रूप से यह विचार किया जाय कि अपेक्षाकृत अधिक अच्छी और सुनिश्चित योजनाएं तैयार करके सामग्री की अधिक-मूल्यवस्था करके जिन मामलों में उपस्कर्तों की परिचालन लागत अधिक हो वहां यांत्रिक उपस्कर्तों पर निर्भरता को कम करके और उपरी तथा प्रणासनिक खर्चों में कमी करके, कहां तक खर्च कम किया जा सकता है।
- (ग) डी० जी० बी० आर० की नयी दर-मूल्की जिन पूर्वानुमानों और आधारों पर बनाई गई है, तथा उसमें प्रतिष्ठित जोड़ने की जो प्रणाली है, क्या वे सब उपयुक्त हैं? प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक पूर्वानुमान एवं आधार की विशद्धता की जांच की जाय। क्या वे दरें अखिल भारतीय अथवा क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और किन्तु समय बाद इन्हें परिशोधित किया जाना चाहिए?
- (घ) क्या जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के साधनों—जनशक्ति और उपकरणों का वर्ष के दौरान किसी भी समय पूरा उपयोग नहीं किया गया है और यदि ऐसा है तो उनका पूरा या अधिकाधिक उपयोग करने के लिए समिति क्या सुझाव देगी?
- (ङ) क्या कृतिक बल (टास्क फोर्स) (सङ्कों के कटाव और रख-रखाव दोनों के लिए) का वर्तमान गठन उपयुक्त है, अथवा कार्य निपादन के स्वरूप पर

प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना खर्च में किफायत किये जाने के विचार से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है?

(c) अत्यधिक किफायती तरीकों का उपयोग किए जाने और उपलब्ध साधनों का यथा सम्भव पूर्ण उपयोग किए जाने की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिए वह समिति वास्तविक निर्माण के दौरान होने वाले व्यय और कार्य निष्पादन की लगातार पुनरीक्षा के बारे में किए जाने वाले उपायों पर विचार करेगी और इस हेतु अपनी सिफारिशें देगी।

समिति का मुख्यालय खिली में होगा लेकिन अपने इस काम के सम्बन्ध में वह जहाँ आवश्यक हो, जाकर निरीक्षण कर सकती है।

समिति अपना कार्य तत्काल शुरू कर देगी और छ: माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

Border Roads Development Board

RESOLUTION

New Delhi, the 14th October 1970

No. F.4(19)/BRDB/Proj./64.—The question of bringing down the cost of departmental construction of roads entrusted to the General Reserve Engineer Force has been under consideration of the Government for some time. This has assumed added importance on account of general increase in cost both of labour and material. It has, therefore, been decided that a thorough examination should be undertaken by a Committee constituted as indicated below, of the various factors which are responsible for the present cost of construction and maintenance of border roads by the GREF and to suggest measures to bring it down, as far as possible, without sacrificing speedy execution or the efficiency of work.

COMPOSITION

Chairman

- Shri S. N. Sinha, Director-General (Roads Development) & Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport.

Members

- Shri S. K. Chhibber, Secretary, Border Roads Development Board.
- Shri A. P. V. Krishnan, Joint Secretary, (Pay Commission & Labour), Ministry of Finance.
- Major General J. S. Bawa, AVSM Director General Border Roads.
- Shri H. C. Malhotra, Chief Engineer I, P.W.D., Himachal Pradesh Government, Simla.

Shri V. P. Dang, Deputy Secretary, Border Roads Development Board, will be the full-time Secretary of the Committee.

TERMS OF REFERENCE

The Committee will examine and report on :—

- whether having due regard to the conditions prevailing in the border areas, the cost of construction and maintenance of roads by Border Roads Organisation are reasonable. If not, what are the factors contributing to the high cost? Are they comparable to the cost of construction and maintenance of comparable roads by other agencies like P.W.D.?

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग-I खण्ड-1 में प्रकाशित किया जाए।

एस० के० छिब्बर, सचिव
सीमा सड़क विकास बोर्ड

अम, रोजगार सम्पर्क संवालय

(भ्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टूबर 1970

सं० 2/11/70-फ० क०—राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के नियमों एवं विनियमों के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसार में, भारत सरकार ने श्री बागाराम तुलपुजे, मिलमजदूर सभा, बम्बई को 5 अक्टूबर, 1970 में अगला आदेश जारी होने तक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के शासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है।

जे० डी० तिवारी, अवर सचिव

- What are the measures—temporary and long-term—which can be taken to reduce the cost of construction and maintenance of roads. In this connection, it may be specifically examined how far the cost can be reduced by better and firm forward programming, improved material management, decreased dependence on mechanical equipment where the operational cost of the equipment is heavy and by reduction in overheads and administrative expenditure.
- Whether the assumptions/bases on which the latest DGBR Schedule of Rates have been framed and the practice of adding percentages thereto are reasonable? The correctness of each of these assumptions/bases may be examined with reference to variable data. Should these rates be prescribed on all-India basis or regionally? At what intervals should they be revised?
- Whether there is under-employment of GREF resources—manpower as well as equipment—at any time of the year and if so, what measures would the Committee suggest to eliminate/reduce it?
- Whether the existing set up of Task Forces (both for formation cutting and maintenance) is suitable or any changes can be made to achieve economies without any adverse effect on the quality of output.
- The Committee may consider measures and make recommendations for continuous review of expenditure and performance during the course of actual construction for ensuring that most economical methods are used and fullest possible utilisation of available resources is made.

The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places as may be necessary in connection with its work.

The Committee will commence work immediately and submit its report within six months.

ORDER

ORDERED that resolution be published in the Gazette of India, Part I Section 1.

S. K. CHHIBBER, Secy.,
Border Roads Development Board

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND
REHABILITATION**
(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 31st October 1970

No. 2/14/70-F.4C.—In pursuance of clause (b) of Rule 7
of the Rules and Regulations of the National Safety Council,

The Government of India have nominated Shri Bagaram
Sulpule, Mill Mazdoor Sabha, Bombay, as the Chairman of
the Board of Governors of the National Safety Council with
effect from the 5th October 1970 until further orders.

J. D. TEWARI, Under Secy.

